राष्ट्रीय इलेक्शन वॉच
प्रेस नोट दि. 1.2.09

चुनाव व राजनिती सुधार पर राष्ट्रीय संमेलन व्दारा इलेक्शन वॉच नेटवर्क व्दारा पांचवे राष्ट्रीय संमेलन मे सर्व सम्मती से यह प्रस्ताव पास किया की राजनिती मे अपराधीयोंके प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

चुनाव व राजनितीक सुधार के पॉचवे दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 31 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एन गोपालस्वामी ने किया। उसका समापन 1फरवरी को हुआ। इस सम्मेलन मे 28 राज्यों से 200 से अधिक नागरिकोंका इलेक्शन वॉच समूह गैर सरकारी संघटन सरकारी अधिकारी व सक्रिय कार्यकर्ताओंने भाग लिया। यह सम्मेलन मुंबई के नेहरू सेंटर मे आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान श्री एन गोपालस्वामीने इस बातपर जोर दिया कि वर्तमान मे चुनाव मे गलत प्रवृतिया प्रवेश करती जा रही है। चुनाव मे माफिया व पैसो का प्रयोग हो रहा है। अशिक्षीत मतदाताओंको शराब एवं अन्य सामुग्री बाटकर लुभाया जाता है। मीडिया का भी दुरूपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग के सामने भी कई चुनौतिया है। इसका ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा की शहरोंमे मतदाताओंकी उदासीनता गंभीर समस्या है। उन्होने कहा की अभी दो सुधार किए गए है। एक फोटो चुनाव सुची व नया मेट्रो मॅनेजमेंट के जरीये जगहे बदलने वाले मतदाताओंकी सुचना व ज्यादा मतदान की समस्या का निदान हो सकेगा।
इस सम्मेलन मे अन्य प्रमुख व्यक्ति केंद्रिय चुनाव आयुक्त डॉ. कुरेशी, सांसद श्री. सुरेश प्रभू, मुंबई के म्युनिसिपल आयुक्त जयराज फाटक, एन. डी. टी. वी. के श्री. श्रीनिवासन जैन और मजदुर किसान शक्ती संघटनसे श्रीमती अरूणा रॉय ने भी भाग लिया। श्री कुरेशी ने भारतीय प्रजातंत्रके सफल कियान्विति की भरपूर प्रंशंसा की। इससे पुरे विश्व मे भारत को सन्मान मिला है। उन्होने कहा की चुनाव आयोग कुछ सीमातक चुनाव मे मसल पॉवर या माफिया की भूमिका को नियंत्रीत कर पाया है परंतु धन की शक्ती व दुरूपयोग को कम करने मे पुरी सफलता नही मिली है। उन्होंने यह भी कहा की राजनिती व राजनितिज्ञो के प्रति जो नकारात्मक छवी बन रही है उसको समाप्त करना चाहिये। इसमे नागरिक संगठनो व समूह को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये। उन्होने यह भी कहा की कॉरपोरेट से जूडे लोगों की भी सामाजिक जिम्मेदारी है उन्हे भी ये काम करना चाहिए।
विभिन्न सामाजिक आंदोलनो व राजनितिक दलो के सुधार को लेकर गहन मन्थन व विचार विमर्श हुआ। राजनीतिक दलोके धन जुटाने मे पारदर्शकता व दलोंके अंदर आंतरिक प्रजातंत्र को लेकर खार चर्चा हुअी। इस बात पर भी चिंता जताई गई की गलत प्रवृतियों मे मिडाया भी साथ दे रहा है इससे समाचारो पर प्रभाव पड रहा है।
इस सम्मेलन मे सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किए।

1 सार्वजनिक जीवन मे शुचिता व नैतिकता की उच्च परंपरा स्थापित की जानर चाहीए। कोई जिस किसी पर गंभीर आरोप के कारण कोर्ट से चार्ज शीट् किया हो उसे चुनाव मे खडे होने का अधिकार नही होना चाहिए।
2 मतदान मशीन मे एक विकल्प यह होना चाहिए की कोई भी प्रत्याशी चुनाव मे खडे
3 राजनीतीक दलोंको नियमित करने के लिये एक व्यापक कानुन की तुरन्त आवश्यकता है।
इन सबके अलावर मुख्य चुनाव अधिकारोंकी व अलग अलग राज्योंके इलेक्शन वॉच समूहके अनुभव भी बांटे गये। खास कर उन समूहों के अनुभव जहा 2008 मे चुनाव हुअे।
एक अच्छे उदाहरण प्रस्तूत करने की के लिए राष्ट्रीय इलेक्शन वॉचने अपने लिऐ भी एक आचारसंहिताको स्विकार किया। इसमे यह प्रस्ताव स्विकार किया की किसी भी प्रत्याशी या दल के लिये चुनाव प्रचार नही करेंगे न किसा का विरोध करेंगे। इस समूहसे जुडे हुअे लोग अपने आंतरिक कार्य प्रणालीमेभी पारदर्शकता व जबाबदेही का पूरा पाल करेंगे।

Contacts:
Anil Bairwal,
National Coordinator
National Election Watch
Association for Democratic Reforms
National Election Watch
+91 9999310100
anil@adrindia.org

Ajit Ranade
Founder Member
Association for Democratic Reforms
+91 9702215312
ajit.ranade@gmail.com

About NEW

The *National Election Watch (NEW)* is a nationwide campaign comprising of more than 1200 NGO and other citizen led organizations working on electoral reforms, improving democracy and governance in India. The National Election Watch is active in almost all states of India and has done election watch for all states and Lok Sabha elections since ADR, along with couple other organizations, won the PIL in Supreme Court in 2002 to making disclosure of educational, financial and criminal background of electoral candidates mandatory.

About ADR

Association for Democratic Reforms (ADR) is a Non-Political, Non-Partisan and a Non-Governmental Organization whose PIL filed in Dec 1999 culminated in a Supreme Court order on Mar 13, 2003 requiring disclosure of criminal, financial and educational background of all contesting candidates. Since then ADR has done Election Watches in almost all State Assembly and Lok Sabha elections. It continues to works towards strengthening democracy and governance in India by focusing on fair and transparent electoral and political processes. It is currently conducting election watch is all states going for assembly polls.
You can learn more about ADR at: http://www.adrindia.org